हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया

New Delhi	
14 February 2019	PAGE – 11
CIRCULATION – 12,99,672	

आयुष्मान से यूपी में 1.18 करोड़ परिवार लाभान्वित

उत्तर प्रदेश सबसे आगे

उत्तर प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों को होगा योजना से फायदा

उत्तर प्रदेश में कुल 1618 अस्पताल सूचीबद्ध

1425 रोगों का मुफ्त इलाज

सभी जरूरतमंद ले सकेंगे लाभ

इलाज खर्च से बढ़ता है बोझ

आयुष्मान योजना में एक लाख 'आयुष्मान मित्र' भर्ती होंगे

दुनियाभर ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सराहा

गोल्डन कार्ड नहीं फिर भी होगा उपचार

इन्हें मिलेगी सुविधा

मुफ्त इलाज पर अब तक खर्च

• 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई

10.74

50

1425

05

72

1.5

33

29

हेल्पलाइन नंबर 14555

योजना के तहत ऐसे होगा चयन

अस्पताल में ऐसे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश में

1.18

06

01

11

1618

434

1184

उ0प्र0 बजट-2019

111

291

3137.5

नवभारत

PUNE	
14 February 2019	PAGE – 4
CIRCULATION – 36,000	

नवभारत

आयुष्मान भारत के लिए नया कदम

संवाददाता

पुणे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और नैटहेल्थ ने आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई को बढ़ाने के लिए सहयोग की घोषणा की. नैटहेल्थ ने अपने सभी सदस्यों को कार्यक्रम का लाभ उठाने और पीएम-जेएवाई के तहत अपने अस्पतालों के सशक्तिकरण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि सभी भारतीयों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित हो सके. एनएचए और नैटहेल्थ ने एनएचए द्वारा मांगे जाने पर, तकनीकी विशेषज्ञों और इनपुट प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है. यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एनएचए जल्द ही पैकेज दरों की जांच करने का अभ्यास करने और मानक उपचार प्रोटोकॉल/दिशानिर्देशों के विकास करने के साथ शुरुआत करना चाहता है. नैटहेल्थ ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि इसके सदस्य एनएचए और राज्य सरकारों की ओर से मूल्य निर्धारण के अभ्यास और तकनीकी सहायता अनुरोधों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे.

THE ECONOMIC TIMES
WWW.ECONOMICTIMES.COM

New Delhi	
18 February 2019	PAGE – 13
CIRCULATION – 3,99,028	

NHA, NATHEALTH to Tie Up for Ayushman Bharat Rollout

NEW DELHI The National Health Authority is all set to collaborate with apex healthcare body NATHEALTH-Healthcare Federation of India for better implementation of the Ayushman Bharat scheme and get more private hospitals on board. The NHA and NATHEALTH officials recently met in Delhi to discuss tieup to scale up the scheme's impact. "It was decided that NATHEALTH will extend full support and set up a mechanism to provide technical experts and inputs, as and when sought by NHA and the state governments," an official in the know-how said.

जनसत्ता

New Delhi	
18 February 2019	PAGE – 5
CIRCULATION – 1,68,653	

आयुष्मान भारत के बेहतर क्रियान्वयन के लिए

हेल्थकेयर फेडरेशन के साथ काम करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) भारत सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' के बेहतर क्रियान्वयन और अधिक निजी अस्तपालों को इसके साथ जोड़ने के लिए शीर्ष स्वास्थ्य संगठन एनएटीएचईएएलटी-हेल्थकेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा।

एनएचए और एनएटीएचईएएलटीएच के अधिकारियों ने हाल ही में दिल्ली में योजना के प्रभाव को बढ़ाने के मद्देनजर सहयोग पर चर्चा की थी। इसकी जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, 'बैठक के दौरान यह तय किया गया कि एनएटीएचईएएलटीएच पूर्ण समर्थन देगा और तकनीकी विशेषज्ञों एवं इनपुट प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा, जैसा कि एनएचए और राज्य सरकारों द्वारा मांग की गई है।'

उन्होंने कहा, 'गुणवत्ता और सुलभ स्वास्थ्य सेवा पैकेज का विकास पीएम-जेएवाई के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है।' केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इससे देश भर में 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को लाभ होने की संभावना है।

अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज कराया है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता ■ कर्त्तव्य ■ समर्पण

NEW DELHI	
2 February 2019	PAGE – 9
CIRCULATION – 1,71,156	

अंतरिम स्वास्थ्य बजट को डॉक्टर बिरादरी और उद्योग जगत ने सराहा

नई दिल्ली (एसएनबी)। 'स्वस्थ भारत' को अगले दशक के लिए पेश की गई 'परिकल्पना2030' का हिस्सा बनाए जाने का स्वास्थ्य उद्योग क्षेत्र ने स्वागत किया है। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग जगत को बजट में सरकार से ज्यादा राशि मिलने की उम्मीद थी। इस बार हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार ने बीते साल की अपेक्षा इस वर्ष 16 फीसद बढ़ाया है यह एक ऐतिहासिक पहल है।

अपोलो समूह की संयुक्त निदेशक संगीता रेड्डी ने संसद में पेश 2019-20 का अंतरिम बजट आम हो या खास सबकी सेहत सुधारने में कारगर होगा। रेड्डी ने कहा कि अंतरिम बजट में परेशानी रहित स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ स्वस्थ भारत को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है।

सिद्धार्थ

अनिल

आरवी पाराशर

विक्रम

नेटहेल्थ के महासचिव सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने सरकार के आयुष्मान भारत मिशन का दायरा बढ़ाने का स्वागत किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डा. केके अग्रवाल ने कहा कि देश की आजादी के बाद हेल्थ सेक्टर के लिए संभवतः पहली बार केंद्र सरकार ने दरियादिली दिखाई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। मोदी सरकार ने 16 फीसद इस बार बजट बढ़ाया

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) के पूर्व अध्यक्ष एवं एंटी क्वैकरी सेल के चेयरमैन डा. अनिल बंसल ने कहा कि बजट स्वास्थ्य जगत में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश का हेल्थ बजट सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10 फीसद तक होना चाहिए जबकि हमारे देश में हेल्थ पर बजट 1.2 फीसद है। इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए-आयुष) के राष्ट्रीय महासचिव डा. आरवी पाराशर के अनुसार आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता है, अब आम आदमी भी निजी अस्पतालों में इलाज करा सकता है।

लाइफ लाइन हॉस्पिटल के निदेशक डा. विक्रम आई शाह का मानना है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के साथ ही, मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही प्राथमिक जांच की सुविधा में कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप का प्रारंभ में ही पता लगेगा।

the pioneer

NEW DELHI	
2 February 2019	PAGE – 2
CIRCULATION – 6,50,000	

Medical fraternity give mixed reaction

SUGANDHA ■ NEW DELHI

The Budget 2019-20 drew mixed reactions from the medical fraternity on Friday. While some considered it to be beneficial in the long run, for some, it was a wishy-washy affair as it failed to include medical education.

According to NATHEALTH, the inclusion of 'Healthy India' in the Government's 10 key priorities under 'Vision 2030' is one of the key takeaways from Friday's Budget, however, some medical associations called it disappointing.

Daljit Singh, President, NATHEALTH said, "The Vision 2030 announced would be a critical step to stem the tide now. Creating a robust health delivery system for comprehensive wellness of the people would be game changer."

India's Non Communicable Diseases (NCD) burden is rising alarmingly and it is estimated to cost $6 trillion by 2030, he informed. We need to declare war on NCDs and address the critical need for strengthening the Primary Care framework focused on prevention, he said further.

Reacting on Ayushman Bharat Siddhartha Bhattacharya, Secretary General, NATHEALTH said, "We welcome the scaling up plans for the Ayushman Bharat Mission and the government's focus on universal health coverage that improves India's march towards a Swasthya Bharat.

However, we believe it has to be done collaboratively through value based scientific costing driving sustainable pricing supported by improved ecosystem efficiency gains."

On the other hand, Dr Ravi Wankhedkar, Ex-National President of Indian Medical Association (IMA) calling it disappointing said, "No increase in outlay for Health has been there as it remains meager 1 per cent of GDP. IMA persistently has demanded to increase it to minimum 2.5 per cent of GDP."

He added by saying that no announcement on reducing drug prices by adopting the long standing demand of IMA of One Company-One Drug-One Price Policy has been made.

Similarly, Dr GS Grewal of Delhi Medical Association (DMA) said, "Setting up of 22nd AIIMS at Haryana is a gimmick and the budget does not include anything concrete for the medical education."

The budget also invited mixed reactions from the private healthcare providers.

Dr DS Rana, Chairman (Board of Management), Sir Ganga Ram Hospital said, "Increase in funds of Ayushman Bharat is a welcome step but I feel allocation could have more due to the sheer size and magnitude of this scheme.

Government should involve private sector for training and development of manpower for rural hospitals where availability of trained manpower has always been challenging."

Dr Aashish Chaudhry, MD, Aakash Healthcare Super Specialty Hospital also said that the Interim Budget 2019 reaffirms the Government's commitment to improve healthcare systems in the country. With Vision 2030 in place, the Government is expected to provide a new momentum to bigger collaboration among stakeholders, he added.

Earlier in the day, while presenting the budget, Finance Minister Piyush Goyal said that through Ayushman Bharat, around 10 lakh patients have already been benefited through which would have otherwise cost them Rs 3,000 crore.

Lakhs of poor and middle class people are also benefiting from reduction in the prices of essential medicines, cardiac stents and knee implants, and availability of medicines at affordable prices through Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras, the Finance Minister added.

The minister also said that 14 of the 21 AIIMS operating or being established in the country presently have been announced since 2014. He also announced setting up of a new — the 22nd AIIMS in Haryana.

हरियाणा से प्रकाशित
पायनियर
हमेशा सच के साथ
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

NEW DELHI	
2 February 2019	PAGE – 12
CIRCULATION – 65,000	

बजट में सभी को कुछ देने का अच्छा प्रयास

उपभोग बढ़ेगा, पूंजी बाजार के लिए अच्छा: विशेषज्ञ

एजेंसी। नई दिल्ली

विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को प्रत्यक्ष नकदी अंतरण जैसी घोषणाओं से उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा और यह पूंजी बाजार की दृष्टि से भी अच्छा है। विशेषज्ञों ने कहा कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश बजट सभी को कुछ देने का एक अच्छा प्रयास है।

रिलायंस म्यूचुअल फंड के मुख्य निवेश अधिकारी (इक्विटी निवेश) मनीष गुनवानी ने कहा कि आम चुनाव से पहले का आखिरी बजट उपभोग बढ़ाने वाला है। इसमें किसानों और मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। बीएसई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा कि मैं वित्त मंत्री को वृद्धि को प्रोत्साहन वाला बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं। इससे समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। इसमें भारत को 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में दृष्टि है।

इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) के सीईओ संजित प्रसाद ने कहा कि बजट में जिन उपायों की घोषणा की गई है उनका मकसद कृषि क्षेत्र की मदद करना और उसका संरक्षण करना है। इससे आगे चलकर जिंस बाजारों को भी फायदा होगा। एएनएमआई के अध्यक्ष राजेश बहती ने कहा कि स्टाम्प शुल्क को समाप्त करने के बजाय सरकार ने वस्तुत: एक तरह से एक राज्यस्तरीय प्रतिभूति लेनदेन कर लगा दिया है जबकि एसटीटी पहले से लागू है।

एक्सिस वेल्थ मैनेजमेंट के सीईओ अंकुश माहेश्वरी ने कहा कि बजट घोषणाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है।

स्वस्थ भारत को परिकल्पना-2030 का हिस्सा बनाए जाने का उद्योग जगत ने किया स्वागत

नई दिल्ली। स्वस्थ भारत को अगले दशक के लिए पेश की गई परिकल्पना 2030 का हिस्सा बनाए जाने का स्वास्थ्य उद्योग क्षेत्र ने स्वागत किया है।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अगले दशक के लिए ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए 10 महत्वपूर्ण आयामों की एक परिकल्पना प्रस्तुत की। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग जगत को बजट में सरकार से ज्यादा राशि मिलने की उम्मीद थी। अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया में अपोलो हॉस्पिटल समूह की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी ने कहा, अंतरिम बजट में परेशानी रहित स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ स्वस्थ भारत को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने शहर-गांव की दूरी पाटने का लक्ष्य रखा है और गांवों में उनकी आत्मा को बरकरार रखते हुए शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं एक अहम कारक है। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र के संघ नैटहेल्थ ने कहा कि आज के बजट में पेश की गई परिकल्पना-2030 के तहत महत्वपूर्ण 10 आयामों में स्वस्थ भारत को शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नैटहेल्थ के महासचिव सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने सरकार के आयुष्मान भारत मिशन का दायरा बढ़ाने का स्वागत किया।

नवभारत

PUNE	
3 February 2019	PAGE – 12
CIRCULATION – 36,000	

सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाएं

पुणे, सं. देश में एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए और आयुष्मान भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (पीएम-जेएवाय) को अगले स्तर पर ले जाने के लिए शीर्ष स्वास्थ्य सेवा संस्था नेटहेल्थने सरकार से चरण बद्ध तरीके से सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के कवरेज में अनिवार्य रूपसे लाने का आग्रह किया है, जिसके लिए शुरू में संगठित क्षेत्र को कवर किया जाना चाहिए. नेटेहेल्थ ने सरकार को अपनी बजट-पूर्व सिफारिशों में हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन फंडकी शुरुआत का भी सुझाव दिया है और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 'राष्ट्रीय प्राथमिकता' सेक्टर का दर्जा देने की मांग की है. देश में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच बहुत कम होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च बहुत अधिक है.लोगों के स्वास्थ्य के प्रभावी प्रबंधन के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा. नेटहेल्थ के महासचिव सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने कहा, "स्वास्थ्य बीमा का कवरेज कम होने का मुख्य कारण यह है कि वर्तमान में यह वैकल्पिक है.